

Office of Chief Engineer
Commercial Unit



U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.
14th floor, Shakti Bhawan Extn.
Lucknow-226001
Tel. No.- 0522-2288056/2287030
CIN :U40101UP1980SGC005065
E-mail: gm.commercial@uprvunl.org
cecommercialunl@gmail.com

पत्रांक - 307/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0

दिनांक : 06, अगस्त, 2022

मुख्य अभियन्ता (परियोजना प्रमुख),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज, जवाहरपुर
सोनभद्र, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़, एटा।

मुख्य प्रबन्धक (वित्त प्रबन्धन इकाई)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : मा0 विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए घोषित विद्युत रेट शिड्यूल दिनांक 04.08.2022 से लागू करने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु घोषित टैरिफ आदेश दिनांक 20.07.2022, तथा निदेशक (वाणिज्य), उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्रांक 345/एचसी/टैरिफ/2022-23, दिनांक 02.08.2022 के अनुक्रम में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रेट शिड्यूल दिनांक 04.08.2022 से लागू कर दिए गये हैं।

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के उपरोक्त आदेशों को उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 07.01.2019 को सम्पन्न हुई 179वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 84/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य) / एल0एम0वी0-10, दिनांक 01, फरवरी, 2019 के तथा Electricity Act -2003 के The Electricity (Removal of difficulty) Fourth Order, 2005 के अनुपालन में उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस तथा परियोजना कालोनी परिसर में विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु पूर्व में किये गये ऐसे आदेशों की समानता में दिनांक 04.08.2022 से लागू किया जाता है।

कृपया तदनुसार उ0नि0लि0 के सेवारत कार्मिकों के वेतन से प्रति माह विद्युत शुल्क की कटौती सुनिश्चित करने तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस एवं परियोजना के आवासीय परिसर के भीतर रह रहे गैर विभागीय विद्युत उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क नियमानुसार जमा कराने का कष्ट करें।

ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस जो विद्युत शुल्क सीधे उ0प्र0पा0का0लि0/सम्बन्धित डिस्काम में जमा करना चाहते हैं, वह सम्बन्धित वितरण खण्डों में भी अपने निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर सकते हैं।

संलग्नक:-यथोपरोक्त।

(अरविन्द कुमार सिंह)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक - 307/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0

दिनांक : 06, अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वाँ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ/केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

→ File - 64

<p>Office of Chief Engineer Commercial Unit</p>		<p>U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel. No.- 0522-2288056/2287030 CIN : U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org cecommercialunl@gmail.com</p>
--	---	---

पत्रांक - /उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0

दिनांक : , अगस्त, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

5. मुख्य अभियन्ता (मानव संसाधन/तापीय परिचालन/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/पी0पी0एम0एम0/पर्या0 एवं सुरक्षा/नव परि0-जानपद/प्रगति/न्यू कोल ब्लॉक), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नकों सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (उ0प्र0पा0का0लि0/समस्त डिस्काम)।

(अरविन्द कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)



पत्रांक :- /एच0सी0/टैरिफ/2022-23

दिनांक: जुलाई, 02 2022

विषय :- मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2020-21 के टू-अप, वर्ष 2021-22 की ए0पी0आर0 तथा वर्ष 2022-23 के सकल राजस्व आवश्यकता एवं टैरिफ के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध निदेशक

पश्चिमांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पूर्वांचल

विद्युत वितरण निगम लि०

मेरठ/लखनऊ/आगरा/वाराणसी।

प्रबन्ध निदेशक

केस्को

कानपुर।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 20.07.2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए टैरिफ आदेश निर्गत कर दिया गया है। टैरिफ आदेश के अन्तर्गत निर्गत रेट शिड्यूल को लागू करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना दिनांक 28.07.2022 को प्रकाशित हो चुकी है। पुनरीक्षित दरें दिनांक 04.08.2022 से प्रभावी होंगी।

उक्त के तारतम्य में मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्गत टैरिफ आदेश की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि अपने स्तर से अपने डिस्काम के अधीन समस्त अधिकारियों को इसे उपलब्ध कराते हुए पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा करें। अनुमोदित रेट शिड्यूल एवं टैरिफ आदेश मा0 आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक :- यथोपरि।

Dir (P&C) TUL/UNL

प्रबन्ध निदेशक

उ० प्र० रा० वि० उ० नि० लि०

भवदीय,

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

संख्या 345/एच0सी0/टैरिफ/2022-23/तददिनांक :

प्रतिलिपि संलग्नकों सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अमित कुमार श्रीवास्तव)
निदेशक (वाणिज्य)

EE(Comm)-1

No. 365 Dir. (Proj. & Com.)/UNL

272

Date 03.08.2022

Dy. No. 620/UNL/CE(Comm.)

Dated 03.08.2022

03.08.2022
SE(Comm)



BEFORE
THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
LUCKNOW

Quorum

Hon'ble Shri Raj Pratap Singh, Chairman

Hon'ble Shri Kaushal Kishore Sharma, Member

Hon'ble Shri Vinod Kumar Srivastava, Member (Law)

In the matter of:

1. Petition for Truing-Up for FY 2020-21, Annual Performance Review (APR) for FY 2021-22 and Approval of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the FY 2022-23– (Petition No. - 1837 of 2022) of Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. (DVVNL)
2. Petition for Truing-Up for FY 2020-21, Annual Performance Review (APR) for FY 2021-22 and Approval of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the FY 2022-23– (Petition No. - 1835 of 2022) of Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. (MVVNL).
3. Petition for Truing-Up for FY 2020-21, Annual Performance Review (APR) for FY 2021-22 and Approval of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the FY 2022-23– (Petition No. - 1833 of 2022) of Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. (PVVNL).
4. Petition for Truing-Up for FY 2020-21, Annual Performance Review (APR) for FY 2021-22 and Approval of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the FY 2022-23– (Petition No. - 1834 of 2022) of Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd. (PuVVNL).
5. Petition for Truing-Up for FY 2020-21, Annual Performance Review (APR) for FY 2021-22 and Approval of Aggregate Revenue Requirement (ARR) for the FY 2022-23– (Petition No. - 1836 of 2022) of Kanpur Electricity Supply Company Ltd. (KESCO)

..... Petitioners

ORDER

1. As per provisions of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred as 'the Act') and the Tariff Policy, the Commission has notified Uttar Pradesh Electricity Regulatory



Commission (Multi Year Tariff for Distribution & Transmission) Regulations, 2019 (hereinafter referred as 'MYT Regulations, 2019') for determination of tariff for the Transmission and Distribution Licensees. These Regulations are applicable for determination of tariff in all cases covered under these Regulations from April 1, 2020, to March 31, 2025.

2. The primary objective of the Commission is to protect the interest of the consumer and at the same time ensuring recovery of reasonable and justified cost by the utilities. The Commission in the previous Order had taken various steps to protect public interest and provided relief to the consumers and Utilities in the State of Uttar Pradesh.
3. The State-owned Distribution Licensees namely Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Madhyanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Purvanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd., Kanpur Electricity Supply Company Ltd. (hereinafter referred to as "DVVNL", "MVVNL", "PVVNL", "PuVVNL", "KESCO" respectively & collectively called as the State-owned Distribution Licensees / Discoms / Petitioners) had filed the Petitions for determination of True-Up for the FY 2020-21, Annual Performance Review of FY 2021-22 and Aggregate Revenue Requirement and Tariff for FY 2022-23 on March 08, 2022.
4. The Commission having deliberated upon the above Petitions and the subsequent filings by the Petitioners, thereafter admitted the same on April 21, 2022. Further, the Commission also considered the views / comments / suggestions / objections / representations received from the stakeholders during the course of the above proceedings and also in the public hearings held through Video Conferencing (VC) on June 21, 2022, June 22, 2022 and June 24, 2022, and State Advisory Committee meeting held on June 27, 2022. Accordingly, the Commission, in exercise of powers vested under Sections 61, 62, 64 and 86 of the Act, 2003 hereby passes this Order and approves the Rate Schedule applicable which is appended herewith. The detailed Order will be issued shortly and uploaded on Commission's website.
5. The State owned Discoms in accordance with Regulation 5.10 of the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff for Distribution & Transmission)



Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission

Regulations, 2019, shall publish the Tariff approved by the Commission in at least two (2) English and two (2) Hindi daily newspapers having wide circulation in the area of supply and shall put up the approved Tariff on its internet website.

6. The Tariff so published shall be in force after seven days from the date of such publication of the Tariffs and shall, unless amended or revised, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.
7. The Commission directs the Licensees to take appropriate steps to implement the approved Rate Schedule.

(Vinod Kumar Srivastava)

Member (Law)

(Kaushal Kishore Sharma)

Member

(Raj Pratap Singh)

Chairman

Place: Lucknow

Dated: 20.07.2022



RATE SCHEDULE FOR FY 2022-23

Rate Schedule for FY 2022-23

(Applicable for DVVNL, MVVNL, PVVNL, PuVVNL and KESCO)

A. GENERAL PROVISIONS:

These provisions shall apply to all categories unless specified otherwise and are integral part of the Rate Schedule.

1. NEW CONNECTIONS:

All new connections shall be given in kW, kVA, or BHP as agreed to be supplied by the Licensee. Further, if the contracted load (kW / kVA) of already existing consumer is in fractions then the same shall be treated as next higher kW / kVA load. If the contracted load is in kW and is being converted into kVA, the conversion factor of 0.90 will be used ($kVA = kW / 0.90$) for tariff application purposes and the same shall be rounded off up to two decimal places.

2. READING OF METERS:

As per applicable provisions of Electricity Supply Code 2005 and its amendments.

3. BILLING WHEN METER IS NOT MADE ACCESSIBLE:

A penalty of Rs. 50.00 / kW or as decided by the Commission through an Order shall be levied for the purposes of Clause 6.2 (c) of the applicable Electricity Supply Code 2005 and its amendments.

4. BILLING IN CASE OF DEFECTIVE METERS:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code 2005 and its amendments.

5. kVAh TARIFF:

'kVAh based tariffs' shall be applicable on all consumers having contracted load of 10 kW / 13.4 BHP and above, under different categories with TVM / TOD / Demand recording meters (as appropriate).

The rates prescribed in different categories in terms of kW and kWh will be converted into appropriate kVA and kVAh by multiplying Fixed / Demand Charges and Energy Charges by an average power factor of 0.90. Similarly, the Fixed / Demand Charges expressed in BHP can be converted into respective kVA rates in accordance with formula given below:

Fixed Charges in kVA = (Fixed Charges in BHP / 0.746) * 0.90

Fixed Charges in kVA = (Fixed Charges in kW * 0.90)

Energy Charges in kVAh = (Energy Charges in kWh * 0.90)



The converted rates (i.e. Energy charge in Rs. / kVAh and Fixed / Demand charges in Rs. / kVA) will be rounded up to two decimal places.

Further, for converting energy slabs of different categories specified in kWh to kVAh, average power factor of 0.90 will be used as a converting factor for converting each energy slab (specified in kWh) into energy slabs (in kVAh). The converted energy slabs (in kVAh) will be rounded to next higher kVAh.

Note 1: In case of kVAh billing only kVAh reading will be used for billing purpose.

Note 2: If the average power factor of a consumer in a billing cycle is leading and is within the range of 0.95 - 1.00, then for tariff application purposes such leading power factor shall be treated as unity. The bills of such consumers shall be prepared on kwh basis. However, if the leading power factor is below 0.95 (lead) then the consumer shall be billed as per the kVAh reading indicated by the meter. However, the aforesaid provision of treating power factor below 0.95 (lead) as the commensurate lagging power factor, for the purposes of billing, shall not be applicable on HV-3 category and shall be treated as unity. Hence, for HV-3, "lag only" logic of the meter should be used which blocks leading kVAh.

6. BILLABLE LOAD / DEMAND:

For all consumers having TVM / TOD / Demand recording meters installed, the billable load / demand during a month shall be the actual maximum load / demand as recorded by the meter (can be in parts of kW or kVA) or 75% of the contracted load / demand (kW or kVA), whichever is higher.

In case the Licensee's meter reader does not note the actual maximum load / demand, then the Licensee will raise the bill at 75% of the contracted load and in cases where the consumer approaches the Licensee with a meter reading but does not provide the proof of actual maximum load / demand displayed on his meter, then in such case the Licensee will raise the bill at 100% of the contracted load.

Further in case a consumer feels that his maximum load / demand reading has been noted wrong, the consumer may approach the licensee with a photo of the actual maximum load / demand reading displayed on his meter of the concerned month. The Licensee shall accept the same for the purpose of computation of billable demand, however if the Licensee wishes to, it can get the same verified within 5 days.

7. SURCHARGE / PENALTY:

(i) DELAYED PAYMENT:

If a consumer fails to pay his electricity bill by the due date specified therein, a late payment surcharge shall be levied at 1.25% on the dues (excluding late payment surcharge) per month; up-to first three months of delay and subsequently at 2.00% on the dues (excluding late payment surcharge) per month of delay. Late payment surcharge shall be calculated proportionately for the number of days for which the payment is delayed beyond the due date specified in the bill and levied on the unpaid amount of the bill excluding delayed payment surcharge. Imposition of this

sf

81

Jan



surcharge is without prejudice to the right of the Licensee to disconnect the supply or take any other measure permissible under the law.

(ii) CHARGES FOR EXCEEDING CONTRACTED DEMAND:

- a) If the maximum load / demand in any month of a **domestic consumer** having TVM / TOD / Demand recording meter exceeds the contracted load / demand, then such excess load / demand shall be levied equal to 100% of the normal rate apart from the normal fixed / demand charge as per the maximum load / demand recorded by the meter. Further, if the consumer is found to have exceeded the contracted load / demand for continuous previous three months, the consumer shall be served a notice of one month advising him to get the contracted load enhanced as per the provisions of the Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof. However, the consumer shall be charged for excess load for the period the load is found to exceed the contracted load. The Licensee shall merge the excess load with the previously sanctioned load, and levy additional charges calculated as above, along with additional security. Subsequent action regarding the increase in contracted load, or otherwise shall be taken only after due examination of the consumer's reply to the notice and a written order in this respect by the Licensee.
- b) If the maximum load / demand in any month, for the consumers of **other category (except (a) above)** having TVM / TOD / Demand recording meter exceeds the contracted load / demand, then such excess load / demand shall be levied equal to 200% of the normal rate apart from the normal fixed / demand charges as per the maximum load / demand recorded by the meter.
- c) Any surcharge / penalty shall be over and above the minimum charge, if the consumption bill of the consumer is being prepared on the basis of minimum charge.
- d) Provided where no TVM / TOD / Demand recording meter is installed, the excess load / demand charge shall be levied as per the Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time.

8. POWER FACTOR SURCHARGE:

- i. Power factor surcharge shall not be levied where consumer is being billed on kVAh consumption basis.
- ii. It shall be obligatory for all consumers to maintain an average power factor of 0.90 or more during any billing period. No new connections of motive power loads / inductive loads above 3 kW, other than under LMV-1 and LMV-2 category, and / or of welding transformers above 1 kVA shall be given, unless shunt capacitors



having I.S.I specifications of appropriate ratings are installed, as described in - 'LIST OF POWER FACTOR APPARATUS' of annexed to this Rate Schedule.

- iii. In respect of the consumers with or without TVM / TOD / Demand recording meters, excluding consumers under LMV-1 category up to contracted load of 10 kW and LMV-2 category up to contracted load of 5 kW, if on inspection it is found that capacitors of appropriate rating are missing or in-operational and Licensee can prove that the absence of capacitor is bringing down the power factor of the consumer below the obligatory norm of 0.90; then a surcharge of 15% on the 'RATE' shall be levied on such consumers. The Licensee may also initiate action under the relevant provisions of the Electricity Act, 2003, as amended from time to time.

Notwithstanding anything contained above, the Licensee also has a right to disconnect the power supply, if the power factor falls below 0.75.

- iv. Power factor surcharge shall however, not be levied during the period of disconnection on account of any reason whatsoever.

9. PROTECTIVE LOAD AND PROTECTIVE LOAD CHARGE:

Consumers getting supply on independent feeder at 11 kV & above voltage, emanating from sub-station, may opt for facility of protective load and avail supply during the period of scheduled rostering imposed by the Licensee, except under emergency rostering. An additional charge @ 100% of base demand charges shall be levied on the sanctioned protective load (as per Electricity Supply Code, 2005 and its amendments) per month as protective load charge. However, consumers of LMV-4 (A) - Public Institutions will pay the additional charge @ 25% of base demand charges only. During the period of scheduled rostering, the load shall not exceed the sanctioned protective load. In case the consumer exceeds the sanctioned protective load during scheduled rostering, he shall be liable to pay twice the prescribed additional charges for such excess load.

10. ROUNDING OFF:

All bills will be rounded off to the nearest rupee i.e. up to 49 paisa shall be rounded down to previous rupee and 50 paisa upwards shall be rounded up to next rupee. The difference due to such rounding shall be adjusted in subsequent bills.

11. OPTION OF MIGRATION TO HV-1 & HV-2 CATEGORY:

The consumer under LMV-2 and LMV-4 with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-1 category and LMV-6 consumers with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-2 category. Furthermore, the consumers shall have an option of migrating back to the original category on payment of charges prescribed in Cost Data Book for change in voltage level.

12. PRE-PAID METERS / AUTOMATIC METER READING SYSTEM:



- (i) Any consumer having prepaid meters shall also be entitled to a discount of 2.00 % on the 'RATE' as defined in the Tariff Order.
- (ii) The token charges for code generation for prepaid meters shall be Rs. 10.00/- per token or as decided by the Commission from time to time.

13. CONSUMERS NOT COVERED UNDER ANY RATE SCHEDULE OR EXPRESSLY EXCLUDED FROM ANY CATEGORY:

For consumers of light, fan & power (excluding motive power loads) not covered under any rate schedule or expressly excluded from any LMV rate schedule will be categorized under LMV-2.

- 14.** A consumer under metered category may undertake any extension work, in the same premises, on his existing connection without taking any temporary connection as long as his demand does not exceed his contracted demand and the consumer shall be billed in accordance with the tariff applicable to that category of consumer.

15. REBATE ON PAYMENT ON OR BEFORE DUE DATE:

A rebate at the rate of 1.00 % on the 'RATE' shall be given in case the payment is made on or before the due date. However, a rebate at the rate of 5.00% on the 'RATE' shall be given to LMV-5 (Rural) (i.e. PTW Rural Category Agricultural Consumers) category of electricity consumers in case the payment is made on or before the due date. The consumers having any arrears in the bill shall not be entitled for this rebate. The consumers who have made advance deposit against their future monthly energy bills shall also be eligible for the above rebate applicable on the 'RATE'.

16. SCHEME FOR ADVANCE DEPOSIT FOR FUTURE MONTHLY ENERGY BILLS:

If a consumer intends to make advance deposit against his future monthly energy bills, the Licensee shall accept such payment and this amount shall be adjusted only towards his future monthly energy bills. On such advance deposit the consumers shall be paid interest, at the interest rate applicable on security deposit, for the period during which advance exists for each month on reducing balance method and amount so accrued shall be adjusted in the electricity bills which shall be shown separately in the bill of each month. Further, quarterly report regarding the same must be submitted to the Commission.

17. FACILITATION CHARGE FOR ONLINE PAYMENT:

- (i) No transaction charge shall be collected from the consumers making their payment through internet banking.
- (ii) The Licensees shall bear the transaction charges for transactions up to Rs. 4,000.00 for payment of bill through internet using Credit Card / Debit Card.

18. MINIMUM CHARGE:

Minimum charge is the charge in accordance with the tariff in force from time to time and come into effect only when sum of Fixed / Demand Charges and Energy Charges are less than a certain prescribed amount i.e. Minimum Charges. For each month, consumer will pay an amount that is higher of the following:



- Fixed / Demand Charges (if any) plus Energy Charge on the basis of actual consumption for the month and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, Fuel Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.
- Monthly minimum charge as specified by the Commission and computed at the contracted load and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, Fuel Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.

19. INTEREST ON DUES PAYABLE TO CONSUMER BY THE LICENSEE:

If a consumer becomes eligible for dues from the Licensee which may arise out of rectification / adjustment / settlement of bill(s), then such consumer will also be entitled to get interest at rate applicable for interest on security deposits on all the dues payable by the Licensee to the consumer. The Licensee shall compute the interest amount for the period during which such pending amounts exists and adjust such interest towards the future monthly bills of consumers. After adjustment of the interest amount in a particular month, the balance amount, will be carried forward to next month for adjustment with interest on balance amount. The details of such interest amount and adjustment made during the month shall be shown separately in the bill. Further, separate accounting of interest paid must be maintained by the Licensees.

20. DEFINITION OF RURAL SCHEDULE:

Rural Schedule means supply schedule as defined and notified by State Load Despatch Centre (SLDC), Lucknow from time to time.

21. GREEN ENERGY TARIFF:

- a. The Commission had computed the Green Energy Tariff payable by opting consumers as Rs. 0.54 per kWh.
- b. This Tariff will be applicable for all the opting consumers except domestic and agriculture consumers. This Tariff will be in addition to the regular Tariff as approved by the Commission.
- c. However, such consumption cannot be taken into consideration in the RPO fulfilment of such consumers if any.
- d. The consumer can request for opting out, however the same shall only be come into force after the issuance of Commission's next Tariff Order.
- e. Further, the Licensees will display the same separately in the bill as well as in the receipt of such consumers who opted for Green Energy Tariff, in addition to the Fixed / Demand Charges and Energy Charges. They will also keep a separate account for this tariff and separate item in their annual financial statements and provide the full details to the Commission every year along with the tariff filings.



B. RETAIL TARIFFS FOR FINANCIAL YEAR 2022-23

RATE SCHEDULE LMV – 1:

DOMESTIC LIGHT, FAN & POWER:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply to:

- a) Premises for residential / domestic purpose, Accommodation for Paying Guests for Domestic purpose (Excluding Guest Houses), Janata Service Connections, Kutir Jyoti Connections, Jhuggi / Hutments, Places of Worship (e.g. Temples, Mosques, Gurudwaras, Churches) and Electric Crematoria, Shelter Homes, orphanages, old age homes, Institutions run for mentally retarded and forsaken children. Non-commercial places occupied by religious persons, of any religion, are also entitled in this category, for a maximum load up to 5 kW, subject to the condition that such non-commercial place shall have a valid registration/recognition from a charitable trust.
- b) Mixed Loads
 - i. **50 kW and above**
 - a. Registered Societies, Residential Colonies / Townships, Residential Multi-Storied Buildings with mixed loads (getting supply at single point) with the condition that at least 70% of the total contracted load shall be exclusively for the purposes of domestic light, fan and power. The above mixed load, within 70%, shall also include the load required for lifts, water pumps and common lighting,
 - b. Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).
 - ii. **Less than 50 kW**

Except for the case as specified in Regulation 3.3 (e) of Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time, if any portion of the load is utilized for conduct of business for non-domestic purposes, then the entire energy consumed shall be charged under the rate schedule of higher charge.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code, 2005 and its amendments.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed during the billing period applicable to the category:



(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule':

1. **Lifeline consumers:** Consumers with contracted load upto 1 kW, energy consumption up to 100 kWh / month.

Description	Tariff Excluding Subsidy		Subsidy (as per GoUP Letter No. 703/24-1-2022-1307/2020 Dated 07.06.2022) and Cross Subsidy		Tariff Payable	
	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
	A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
Load upto 1 kW and for consumption up to 100 kWh / month	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 3.50 / kWh	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 3.00 / kWh

2. **Others:** Other than Lifeline consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid above for lifeline consumers)

Description	Tariff Excluding Subsidy		Subsidy (as per GoUP Letter No. 703/24-1-2022-1307/2020 Dated 07.06.2022) and Cross Subsidy		Tariff Payable	
	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
	A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
i) Un-Metered	Rs. 935.00 / kW / month	-	Rs. 435.00 / kW / month	-	Rs. 500.00 / kW / month	-



Description	Consumption Range	Tariff Excluding Subsidy		Subsidy (as per GoUP Letter No. 703/24-1-2022-1307/2020 Dated 07.06.2022) and Cross Subsidy		Tariff Payable	
		Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
		A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
ii) Metered	Upto 100 kWh / month	Rs. 90.00/ kW / month	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 3.15 / kWh	Rs. 90.00/ kW / month	Rs. 3.35 / kWh
	101 - 150 kWh / month		Rs. 6.50 / kWh		Rs. 2.65 / kWh		Rs. 3.85 / kWh
	151 – 300 kWh / month		Rs. 6.50/ kWh		Rs. 1.50/ kWh		Rs. 5.00 / kWh
	Above 300 kWh / month		Rs. 6.50 / kWh		Rs. 1.00/ kWh		Rs. 5.50 / kWh

(b) Supply at Single Point for bulk loads (50 kW and above, Supplied at any Voltage):

Description	Fixed Charge	Energy Charge
For Townships, Registered Societies, Residential Colonies, multi-storied residential complexes (including lifts, water pumps and common lighting within the premises) with loads 50 kW and above with the restriction that at least 70% of the total contracted load is meant exclusively for the domestic light, fan and power purposes and for Military Engineer Service (MES) for Defence Establishments (Mixed load without any load restriction).	Rs. 110.00 / kW / Month	Rs. 7.00 / kWh

The body seeking the supply at Single point for bulk loads under this category shall be considered as a deemed franchisee of the Licensee.

The deemed franchisee is required to provide to all its consumers and the licensee, a copy of the detailed computation of the details of the amounts realized from all the individual consumers and the amount paid to the licensee for every billing cycle on half yearly basis. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee shall arrange to get its account(s) audited by a Chartered Accountant mandatorily. The audited accounts will be made available to all the consumers of the deemed



franchisee within 3 months of the closure of that financial year. If he fails to do so, then the consumers may approach the Consumer Grievance Redressal Forum (CGRF) having jurisdiction over their local area for the redressal of their grievances.

The deemed franchisee should separately meter the electricity supplied from back up arrangements like DG sets etc. The bill of its consumers should clearly depict the units and rate of electricity supplied through back up arrangement and electricity supplied through Licensee.

The deemed franchisee shall not disconnect the supply of electricity of its consumers on the pretext of defaults in payments related to other charges except for the electricity dues regarding the electricity consumed by its consumers and electricity charges for lift, water lifting pump, streetlight if any, corridor / campus lighting and other common facilities.

In case the deemed franchisee exceeds the contracted load / demand under the provisions of Clause 7(ii) – 'Charges for Exceeding Contracted demand' of the General Provisions of this Rate Schedule, only in such case the deemed franchisee will recover the same from the individual members who were responsible for it on the basis of their individual excess demands.

(c) OTHER METERED DOMESTIC CONSUMERS:

- 1. Lifeline consumers:** Consumers with contracted load of 1 kW, energy consumption up to 100 kWh / month.

Description	Tariff Excluding Subsidy		Subsidy (as per GoUP Letter No. 703/24-1-2022-1307/2020 Dated 07.06.2022) and Cross Subsidy		Tariff Payable	
	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
	A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
Load upto 1 kW and for consumption up to 100 kWh / month	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 3.50 / kWh	Rs. 50.00 / kW / month	Rs. 3.00 / kWh



2. **Others:** Other than Lifeline consumers (i.e. consumers who do not qualify under the criteria laid above for lifeline consumers).

Description	Consumption Range	Tariff Excluding Subsidy		Cross Subsidy		Tariff Payable	
		Fixed Charge	Tariff Excluding Subsidy	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
		A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
Metered	Upto 100 kWh / month	Rs. 110.00 / kW / month	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 1.00 / kWh	Rs. 110.00 / kW / month	Rs. 5.50 / kWh
	101 - 150 kWh / month		Rs. 6.50 / kWh		Rs. 1.00 / kWh		Rs. 5.50 / kWh
	151- 300 kWh / month		Rs. 6.50 / kWh		Rs. 0.50 / kWh		Rs. 6.00 / kWh
	Above 300 kWh / month		Rs. 6.50 / kWh		-		Rs. 6.50 / kWh

Note: For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer, then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data of maximum demand.

2

2

2

**RATE SCHEDULE LMV – 2:****NON - DOMESTIC LIGHT, FAN AND POWER:****1. APPLICABILITY:**

This schedule shall apply to all consumers using electric energy for Light, Fan and Power loads for Non-Domestic purposes, like all type of Shops including Patri Shopkeepers, Hotels, Restaurants, Private Guest Houses, Private Transit Hostels, Private Students Hostels, Marriage Houses, Show-Rooms, Commercial / Trading Establishments, Cinema and Theatres, Banks, Cable T.V. Operators, Telephone Booths / PCO (STD / ISD), Fax Communication Centres, Photo Copiers, Cyber Café, Private Diagnostic Centres including X-Ray Plants, MRI Centres, CAT Scan Centres, Pathologies and Private Advertising / Sign Posts / Sign Boards, Commercial Institutions / Societies, Automobile Service Centres, Coaching Institutes, Private Museums, Power Looms with less than 5 kW load and for all companies registered under the Companies Act, 1956 with loads less than 75 kW.

2. Character and Point of Supply:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code, 2005 and its amendments.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed during the billing period applicable to the category:

(a) Consumers getting supply as per 'Rural Schedule'

Description	Tariff Excluding Subsidy		Cross Subsidy		Tariff Payable	
	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge	Fixed Charge	Energy Charge
	A	B	A1	B1	= A - A1	= B - B1
Metered	Rs. 110.00 / kW / month	Rs. 6.50 / kWh	-	Rs. 1.00 / kWh	Rs. 110.00 / kW / month	Rs. 5.50 / kWh

(b) In all other cases, including urban consumers and consumers getting supply through rural feeders but exempted from scheduled rostering / restrictions or through co-generating radial feeders in villages / towns.



Contracted Load	Fixed Charge	Consumption Range	Energy Charge
Up to 4 kW	Rs. 330.00 / kW / month	Upto 300 kWh / month	Rs. 7.50 / kWh
		Above 300 kWh / month	Rs. 8.40 / kWh
Above 4 kW	Rs. 450.00 / kW / month	Upto 1000 kWh / month	Rs. 7.50 / kWh
		Above 1000 kWh / month	Rs. 8.75 / kWh

* Minimum charge payable by a consumer under the category "(b) In all other cases" shall be Rs. 600.00 / kW / month (From April to September) and Rs. 475.00 / kW / month (From October to March).

Note: For all consumers under this category the maximum demand during the month recorded by the meter has to be essentially indicated in their monthly bills. However, this condition would be mandatory only in case meter reading is done by the Licensee. Accordingly, if the bill is being prepared on the basis of reading being submitted by the consumer, then the consumer would not be liable to furnish maximum demand during the month and his bill would not be held back for lack of data on maximum demand.

4. REBATE TO POWER LOOMS:

Rebate to Power Loom consumers shall be provided in accordance with the applicable Government orders subject to adherence of provision of advance subsidy.



RATE SCHEDULE LMV – 4:

LIGHT, FAN & POWER FOR PUBLIC INSTITUTIONS AND PRIVATE INSTITUTIONS:

1. APPLICABILITY:

Applicable for load less than 75 kW.

LMV- 4 (A) - PUBLIC INSTITUTIONS:

This schedule shall apply to:

- (a) Government Hospitals / Government Research Institutions / Offices of the Government Organizations other than companies registered under Companies Act 1956.
- (b) Government & Government aided (i) Educational Institutions (ii) Hostels (iii) Libraries.
- (c) Religious and charitable trusts & Institutions having a valid registration under Section 12 AA & 80 G issued by the Income Tax department including hospitals, colleges and those providing services free of cost or at the charges / structure of charges not exceeding those in similar Government operated institutions.
- (d) Railway Establishments (excluding railway traction, industrial premises & Metro) such as Booking Centres, Railway Stations & Railway Research and Development Organization, Railway rest houses, Railway holiday homes, Railway inspection houses.
- (e) All India Radio and Doordarshan.
- (f) Guest houses of Government, Semi-Government, Public Sector Undertaking Organisations.

LMV-4 (B) - PRIVATE INSTITUTIONS:

This schedule shall apply to non-Government hospitals, nursing homes / dispensaries / clinics, private research institutes, and schools / colleges / educational institutes & charitable institutions / trusts not covered under (A) above.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code, 2005 and its amendments.

3. RATE:

Rate, gives the fixed and energy charges at which the consumer shall be billed during the billing period applicable to the category:



Rate Schedule for FY 2022-23

Description	Fixed Charge	Energy Charge
(A) For Public Institutions	Rs. 300.00 / kW / month	Rs. 8.25 / kWh
(B) For Private Institutions	Rs. 350.00 / kW / month	Rs. 9.00 / kWh

4

Q

2



RATE SCHEDULE LMV – 10:

DEPARTMENTAL EMPLOYEES AND PENSIONERS:

1. APPLICABILITY:

This schedule shall apply only to such employees (including the cases of retired / voluntary retired or deemed retired) of Licensees / successor entities of erstwhile Uttar Pradesh State Electricity Board (UPSEB), who own electricity connection in their own name and opt for the same for their own use for light, fan and power for domestic appliances, where the energy is being fed directly from Licensee mains. The Schedule shall also apply to spouse of employees served under Licensees / successor entities of erstwhile UPSEB.

2. RATE:

For all such consumers LMV-1 rate schedule will be applicable.

3. ELECTRICITY DUTY:

Electricity duty on the above shall be levied in addition at the rates as may be notified by the State Government from time to time.

4. OTHER PROVISIONS:

- (i) For serving / retired employees and their spouse, the supply will only be given at one place where Licensee's mains exist. The electric supply under this tariff will be given only at one place, within the area of erstwhile UPSEB / its successor companies.
- (ii) Concerned executive engineers will take an affidavit from all employees and pensioners that the electricity supplied to their premises is being used exclusively for the purpose of domestic consumption of themselves and their dependants. It will have to be certified by the employees/pensioners that such electricity is not being used for any other purpose or to any individual to whom his house has been rented out. Without any prejudice to any legal action as provided in the legal framework, any misuse to above effect shall invalidate him from the facility of LMV-10 on permanent basis.
- (iii) In the event of transfer of the employee, this tariff shall be applied at the new place of posting only when a certificate has been obtained from the concerned Executive Engineer of the previous place of posting, that the supply under this tariff has been withdrawn at previous place of posting. Further, the employee shall also be required to submit an affidavit that he is not availing the benefit of LMV-10 connection anywhere else in the state.



- (iv) Those who are not availing this tariff shall also give a declaration to this effect. This declaration shall be pasted / kept in his service book / personal file / Pensioners record. If the declaration is found wrong, necessary action against the employee shall be taken as per the provisions of service rules. If declaration has already been given at the present place of posting then further declaration is not necessary, due to this revision. Pensioners shall also have to give a similar declaration for availing departmental tariff at only one place. In case this declaration is found wrong, this tariff shall be withdrawn forever.
- (v) No other concession shall be admissible on this tariff.
- (vi) The schedule of miscellaneous charges as appended with Licensee's General Tariff as amended from time to time and Electricity Supply (Consumers) Regulation, 1984 as enforced from time to time shall also be applicable on the employee / pensioner receiving supply under this schedule.
- (vii) Retired employees drawing pension from the Treasury / Bank will have to pay the monthly electricity charges as per the rates given in the rate schedule applicable to their category.